*मुद्रास्फीति से जूझना**

रघुराम जी. राजन

मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद ! भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) भारतीय बांड, मुद्रा और व्युत्पन्नी बाज़ारों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वह रिज़र्व बैंक के साथ विभिन्न क्षमताओं में कार्य कर रहा है और हमें उभरती चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान की है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सम्मेलन के सभी सत्र वर्तमान संबंधी है और इसलिए मैंने मुद्रास्फीति जिसकी नियत आय बाज़ारों से सर्वाधिक संबद्धता है, विषय पर बात करना चुना है।

जैसाकि आपको ज्ञात है भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन ''बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना तथा भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित के लिए उसकी मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करने'' हेतु किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य : दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए हितकर मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना तथा एक प्रभावशाली और समावेशी वित्तीय प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना, इन शब्दों में निहित हैं।

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के लिए संभाव्य अत्यधिक संवृद्धि लाने हेतु प्रतिबद्ध है - इस पर हमारे और उत्तरी ब्लॉक के बीच कोई फर्क नहीं है। हमें विश्वास है कि वित्तीय क्षेत्र को विकसित करने के अलावा एक नियत अवधि के दौरान मुद्रास्फीति को घटाकर मौद्रिक स्थिरता के माध्यम से हम वर्तमान स्थिति में संभाव्य सवृंद्धि को उत्तम तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। और विशेष रूप से हम सीपीआई मुद्रास्फीति को जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत तक तथा जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत तक नीचे लाने का इरादा रखते हैं।

यहां कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रथम, क्या हम संवृद्धि की लागत पर मुद्रास्फीति पर काबू पाने का निर्णय ले रहे हैं? अधिकांश लोग यह मानते है कि संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच एक अल्पकालीन लेन-देन है। ब्याज दरें बढ़ाकर भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों को दरें बढ़ाने को प्रेरित करता है और अतः मांग घट जाती है ; जब दरें अधिक हो तो फर्म इतना उधार नहीं लेते हैं कि वे निवेश कर सकें तथा एकल व्यक्ति उधार पर टिकाऊ वस्तुएं खरीदना बंद कर देते हैं और बदले में बचत करने लगते हैं। कम मांग संवृद्धि, मांग और आपूर्ति के बीच एक बेहतर बराबरी अग्रसर करती है और इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं हेतु कम मुद्रास्फीति लेकिन कम संवृद्धि भी प्रदान करती है।

इस संबंध में, यदि कम दरें उच्च मांग और उच्च मुद्रास्फीति उत्पन्न करता है तो लोग शायद अधिक उत्पादन करें यह मानते हुए कि उन्हें और अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है लेकिन उन्हें यह अहसास नहीं है कि उच्च मुद्रास्फीति उन वस्तुओं के मूल्यों को घटाता है जो वे राजस्व में से खरीद सकते हैं। जैसाकि कहावत है ''आप कभी न कभी सभी को मूर्ख बना सकते है'', अचानक मुद्रास्फीति कुछ समय के लिए संवृद्धि बढ़ा सकती है। अतः अल्पावधि में भावार्थ यह है कि उच्च मुद्रास्फीति से उच्च संवृद्धि होती है।

जैसे-जैसे जनता मुद्रास्फीति की उच्चतर स्तर की आदी हो जाती है, जनता को उल्लू बनाने का फिर से एक ही तरीका है, और उच्च मुद्रास्फीति उत्पन्न करना। इसका परिणाम है मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि/कमी (इनफ्लेशनरी स्पाइरल) जो जनता के लिए आश्चर्यजनक कीमत निर्मित करता है। अतः अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया है - पिछले पैराग्राफों में निहित सुझावों के लिए बहु संख्या में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं - कि वे लम्बे समय में संवृद्धि उत्पन्न करने हेतु केन्द्रीय बैंक के लिए सबसे उत्तम तरीका है मुद्रास्फीति को कम करना। कभी न कभी जनता हमेशा यह समझ जाती है कि केन्द्रीय बैंक क्या कर रहा है, क्या वह अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। और यदि जनता यह अपेक्षा करने लगे कि मुद्रास्फीति कम बनी रहेगी तो केन्द्रीय बैंक उल्लेखनीय ढंग से ब्याज दरें कम कर सकता है और इस प्रकार मांग और संवृद्धि को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। वाकई मलेशियन सेन्ट्रल बैंक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आज दरों को कम रख सकता है उसका यही कारण है कि उसने मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है और अपने नागरिकों को दृढ़ विश्वास दिलाया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह मुद्रास्फीतिकारक जंगली (बीस्ट) को हरा देगा यदि उसने अपना सर ऊपर उठाया।

दूसरे शब्दों में, दीर्घकालिक संवृद्धि को उत्पन्न करने के लिए हमें पहले मुद्रास्फीति से लड़ना होगा। मैं आगे यह भी कहूँगा कि जनता का अधिक विश्वास कि मुद्रास्फीति कम होगी से हमारी मुद्रा को स्थिरता मिलेगी और जिस तरह का चक्रावर्तन हमने पिछले ग्रीष्मकाल में देखा उसकी रोकथाम करेगा। कारोबारी संबंध में विनिमय दर स्थिरता केंद्र बिंदु है। यदि हमें मुद्रास्फीति को नीचे लाना है तो हमें

* डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 26 फरवरी, 2014 को मुंबई में फिमडा-पीडीएआई में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन वक्तव्य।

आज ही शुरूआत करनी चाहिए। हम जनता की अपेक्षाओं तक राह नहीं देख सकते कि मुद्रास्फीति और मजबूत होगी तथा मुद्रास्फीति में उत्तरोत्तर वृद्धि/कमी को गति प्राप्त होगी। इसलिए हमने सितंबर से 3 बार ब्याज दरों को बढ़ाया है।

लेकिन उन उद्योगपतियों का क्या जो हमें दरों में कटौती के लिए कहते हैं? मुझे अब भी उस उद्योगपति की प्रतीक्षा है जिसे कम दरें नहीं चाहिए चाहे जो भी दरों के स्तर हों। लेकिन क्या आज एक कम नीतिगत ब्याज दर उन्हें निवेश करने हेतु प्रेरित करेगा? हम भारतीय रिज़र्व बैंक में सोचेंगे कि नहीं। प्रथम हम यह विश्वास नहीं करते कि आज निवेश न करने का मुख्य कारण है उच्च ब्याज दरें। दूसरा, यदि हम दरों में कटौती करें तब भी हम विश्वास नहीं करते कि बैंकों जो उच्चत्तर जमा दरों का भुगतान कर रहे हैं, वे अपनी उधार दरों में कटौती करेंगे। इसका कारण यह है कि एक जमाकर्ता जो उच्च स्फीतिकारी अपेक्षाएं रखता हो वह उन दरों से कम दर के लिए नहीं जाएगा जो उसे बैंक देता है। मुद्रास्फीति जमा दरों पर एक न्यूनतम दर निर्धारित करता है और इस प्रकार उधार दर पर भी निर्धारित करता है।

फिलहाल, अतः हम यह नहीं मानते कि नीतिगत दर उस स्तर पर है जहां वह किसी न किसी तरह मांग को प्रभावित कर सकता है। तथापि, हम यह विश्वास करते हैं कि कमज़ोर अर्थव्यवस्था और मजबूत खाद्य उत्पाद के कारण जैसे-जैसे मुद्रास्फीति नीचे आएगी, नीतिगत दर बैंक ब्याज दर ढाँचे पर और मजबूत प्रभाव डालेगी और मांग को प्रभावित करना शुरू करेगी।

अतः आज हमारे प्रभाव का अधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत है अपेक्षाएं। यदि जनता यह मानती है कि हम मुद्रास्फीति के बारे में गंभीर हैं और मुद्रास्फीति नीचे आने की उनकी अपेक्षाएं हैं तो मुद्रास्फीति भी नीचे आ जाएगी। अवश्य ही कई लोग उनके हाल ही के तथा सबसे प्रमुख अनुभव को केवल व्यापक बनाकर अपेक्षाएं बना लेते हैं। इसलिए हमें अपेक्षाओं को कम करने के लिए खाद्य मूल्य अवस्फीति की वर्तमान घटना से फायदा उठाना चाहिए - अभी कार्रवाई करने हेतु और एक कारण।

चलिए हम उनसे जो चाहते हैं कि हम धीमे जाएं और जवाब देने के बजाय उनकी ओर मुख करें जो हमसे और करने की उम्मीद रखते हैं। यदि हम यह सोचते हैं कि मुद्रास्फीति बहुत महत्त्वपूर्ण है तो क्यों न हम ''वॉकर जैसा'' करें और आसमान छूती दरों को बढ़ाकर तुरंत मुद्रास्फीति को नीचे ला दें? अवश्य ही यदि हम काफी हद तक नीतिगत दरें बढ़ाएं तो बैंकों को भी हमारी बराबरी में दरों को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करने पर शायद मांग में गिरावट आए और मुद्रास्फीति तुरंत नीचे आ जाएगी, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाएगा।

वॉकर्स फेड द्वारा लायी गयी मंदी और तदुपरांत आयी बचत और ऋण संकट को याद करो? एक विकासशील देश अमरीका की तरह लचीली स्थिति में नहीं है। एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था को आघात चिकित्सा (शॉक थिरेपी) देने के बजाय भारतीय रिज़र्व बैंक अवस्फीति को अचानक लाने के बजाय उसे धीरे-धीरे लाने को तरजीह देता है और साथ ही यदि अर्थव्यवस्था प्रक्षेपित पथ से हटती है तो जो भी आवश्यक हो उसे करने के लिए तैयार रहता है। फिलहाल, हम यह मानकर चलते हैं कि दर उचित प्रकार से निर्धारित की गई है।

ऐसे भी लोग हैं जो यह समझते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमने अब तक यह किया है कि पटेल समिति के यथोचित सुझावों को अपनाया है, वह यह कि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के बजाय हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति पर अपने प्राथमिक उद्देश्य के रूप में फोकस कर रहे हैं। पटेल समिति ने एक समय-सीमा का सुझाव दिया है जिसमें मुद्रास्फीति को कम करके 6 प्रतिशत तक लाना है और जो बिना किसी तकलीफ के किया जा सकता है। यदि रिज़र्व बैंक के परामर्श से सरकार का अंतिम निर्णय मिस्त्री, सीएफएसआर, एफएसएलआर और पटेल समितियों की सिफारिशों को अपनाना है, और उद्देश्य यह है कि फोकस मुद्रास्फीति को करना है, तो यह बेहतर होगा कि मध्यकालिक मुद्रास्फीति के लक्ष्य का निर्धारण रिज़र्व बैंक एवं अन्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर कार्यपालक या विधायी द्वारा किया जाए। पटेल समिति की रिपोर्ट जनसाधारण के अभिमत और बहस के लिए प्रकाशित कर दी गई है, और जैसे ही हम उन अभिमतों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण कर लेते हैं, हम उसपर आंतरिक रूप से विचार करेंगे तथा उसके बाद उसपर सरकार से विचार-विमर्श प्रारंभ कर देंगे। इतना सब कुछ कहा जा चुका है, अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह बताते हैं कि बेहतर यह होगा कि, एक बार जब केंद्रीय बैंक का उद्देश्य निश्चित हो जाए और परिचालनगत लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाएं, तो फिर सरकार को चाहिए कि वह प्रविधिविज्ञों को केंद्रीय बैंक में अपना कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहीए।

अंतिम बात, क्या पटेल समिति का इरादा यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक का रुख मुद्रास्फीति के 'कठोर फल' की ओर कर दिया जाए जिसका फोकस, वित्तीय स्थिरता सहित अन्य सभी चीज़ों को छोड़कर केवल मुद्रास्फीति को कम करने पर रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है! मध्यावधि में लचीली मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखने का आशय यह है कि मौद्रिक नीति समिति मध्यावधि में मुद्रास्फीति पर फोकस करेगी; जिसकी चिंता यह होगी कि मुद्रास्फीति न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम हो।

इसका मतलब यह हुआ कि वह मुद्रास्फीति की अस्थायी चुभन (जैसाकि इस नवंबर की संख्या) को अनदेखा कर सकती है किंतु दरें भी बढ़ाती है क्योंकि जब लगातार बनी हुई कम ब्याज दरों और कम मुद्रास्फीति की वजह से वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौती बढ़ जाए - क्योंकि वित्तीय संकट, अपस्फीति की स्थिति पैदा कर सकता है। अन्य शब्दों में, मौद्रिक नीति समिति केवल ब्लिंकर्स पर ध्यान देते हुए महंगाई की संख्या को नहीं देखती रहेगी। अनेक उभरते बाज़ारों ने कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य रखा है, जबकि ''लक्ष्य न रखने वाले'' जैसे फेड अपनी मूल्य स्थिरता के लक्ष्य को एक संख्या प्रदान करने के साथ, मुद्रास्फीति को समग्र रूप से किंतु उसके नाम को लक्ष्य करता है।

मैं, इस बचे हुए समय में एक और मुद्दा प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसका उपयोग अनेक आलोचकों ने किया है - उनका कहना है कि वास्तविक समस्या खाद्यान्न की है, आप यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि इसे नीतिगत दर के माध्यम से कम किया जाए? ऐसे आलोचकों के लिए साधारण सा जवाब यह है कि प्रमुख सीपीआई मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्यान्न और ऊर्जा शामिल नहीं हैं, बहुत अधिक रही है जो सेवाओं में ऊंची मुद्रास्फीति को परिलक्षित करती है। उसे नीचे लाना निश्चित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के दायरे में है। किंतु मेरा तर्क यह है कि नीति अप्रासंगिक नहीं है, यहां तक कि खाद्यान्न संबंधी मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में भी, हालांकि यह भी स्पष्ट है कि इसमें सरकार को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

1. हाल के वर्षों में अनुभव की गई ऊंची मुद्रास्फीति में खाद्य मूल्यों की भूमिका

नये सीपीआई से नापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल 2012 से जनवरी 2014 के दौरान दो अंकों में बनी रही, और उस अवधि में इसका औसत 10 प्रतिशत था। खाद्य-मुद्रास्फीति का सूचकांक में भार 47.6 प्रतिशत था, और हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका हिस्सा सबसे अधिक था (चार्ट 1)। खाद्य मुद्रास्फीति इस अवधि के दौरान दो अंकों में बनी रही, जो कम होकर जनवरी 2014 में जाकर 9.9 प्रतिशत हुई।

2. खाद्य-मूल्य ऊंचे क्यों है?

यद्यपि, घरेलू उत्पादन, 2009-10 तथा 2012-13 को छोड़कर जिसमें स्थिति उलट गई थी, लगातार बढ़ा है किंतु यह खाद्य मूल्यों को नरम बनाने में परिलक्षित नहीं हुआ है। आइए यह समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है।

बढ़ती हुई समृद्धता और आहार में बदलाव

गृहस्थों के उपभोग पर व्यय से संबंधित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पिछले दशक के दौरान समग्र उपभोग में खाद्य पदार्थों का हिस्सा कम होता जा रहा है (चार्ट 2), किंतु इसकी गति खाद्य-मूल्यों में अपेक्षाकृत अत्याधिक वृद्धि की तुलना में धीमी है। इसका मतलब यह है कि मूल्य में परिवर्तन के प्रति मांग की लोच तुलनात्मक रूप से कम है।

चार्ट 1 : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति का योगदान

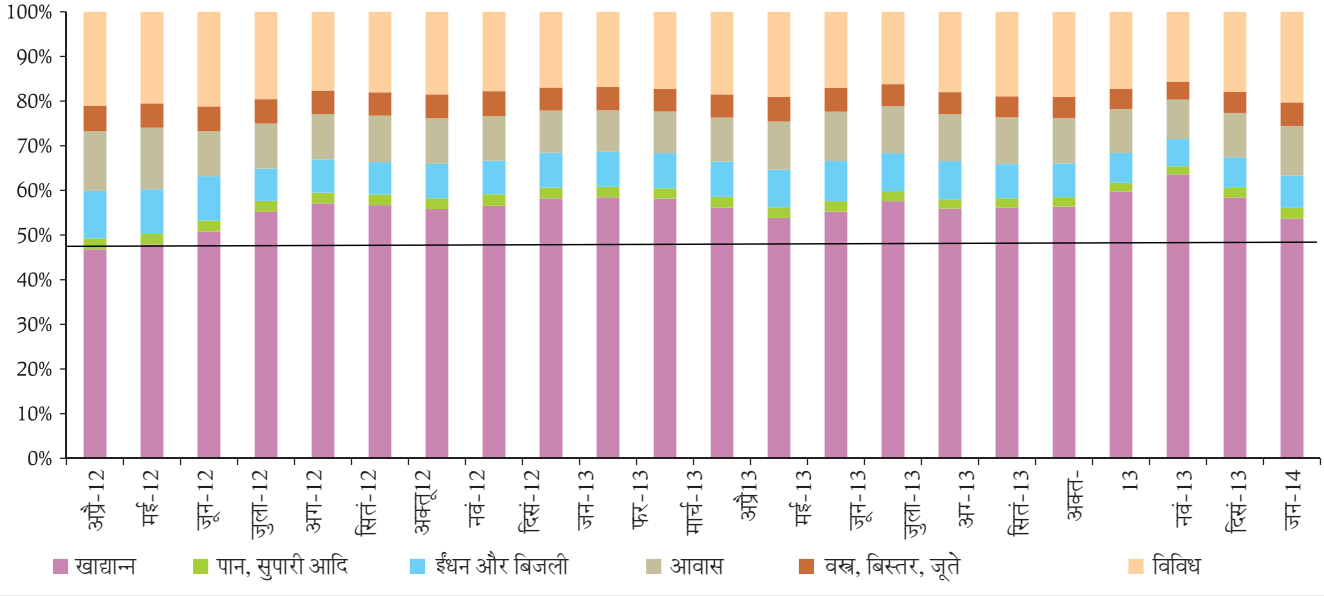

चार्ट 2 : उपभोक्ता आदतों में परिवर्तन

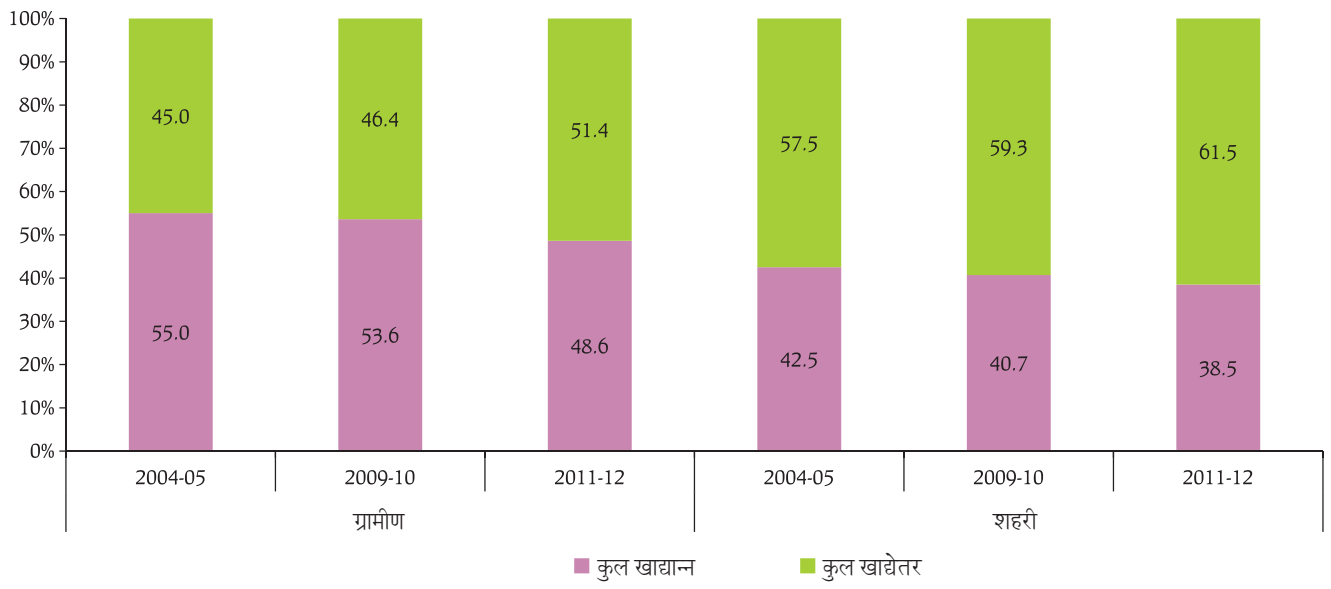

समग्र उपभोग के हिस्से में गिरावट के बावजूद प्रति व्यक्ति वास्तविक खाद्यान्न का उपभोग बढ़ा है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में (चार्ट 3)।

प्रोटीन-युक्त तथा अन्य ऊंचे मूल्य के खाद्यान्नों (चार्ट 4 व 5) के प्रति भी खाने की आदतें विशेष रूप से बदली हैं। इन मदों को हाल के समय में समग्र रूप से खाद्यान्न की कीमतों में इज़ाफा होने में काफी योगदान रहा है।

खाद्यान्न की ऊंची कीमतों की महंगाई के अन्य संभावित कारण

ए. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएससी)

विश्लेषकों ने खाद्यान्न की ऊंची कीमतों की महंगाई का एक स्पष्ट कारण यह बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत अधिक हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा, कृषि लागत और मूल्य संबंधी आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है, जो कई कारकों पर आधारित होता है जिसमें प्राथमिक रूप से उत्पादन की लागत तथा

चार्ट 3 :प्रति व्यक्ति वास्तविक खाद्यान्न का उपभोग

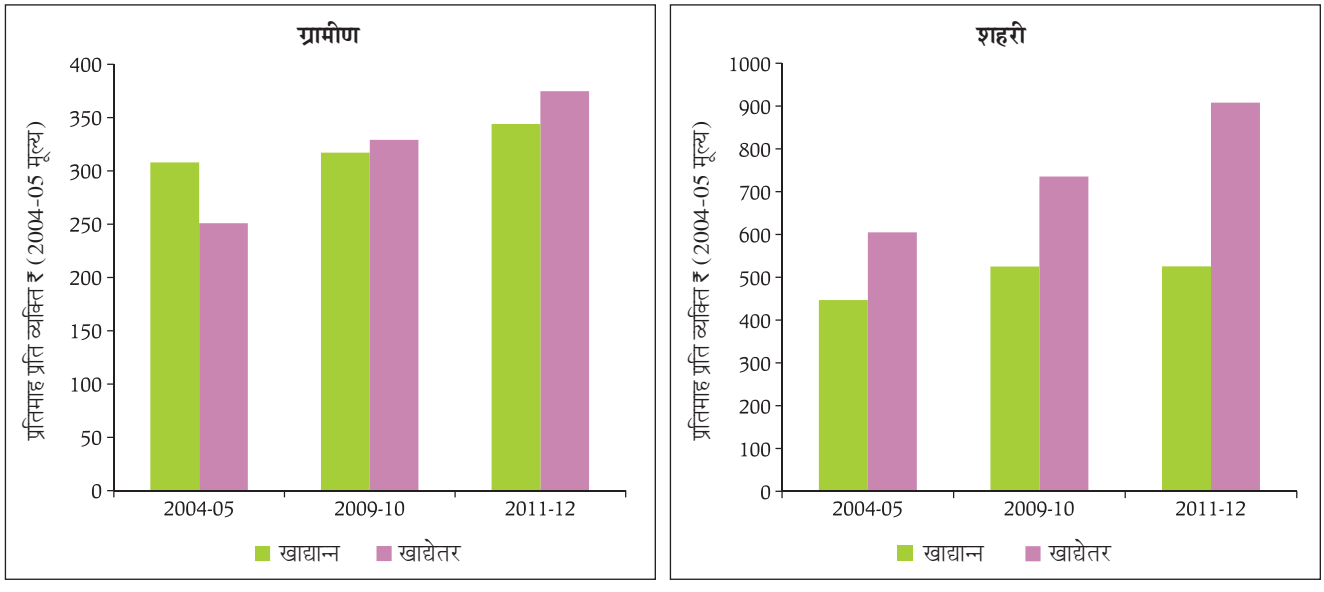

चार्ट 4 :भोजन की आदतों में परिवर्तन

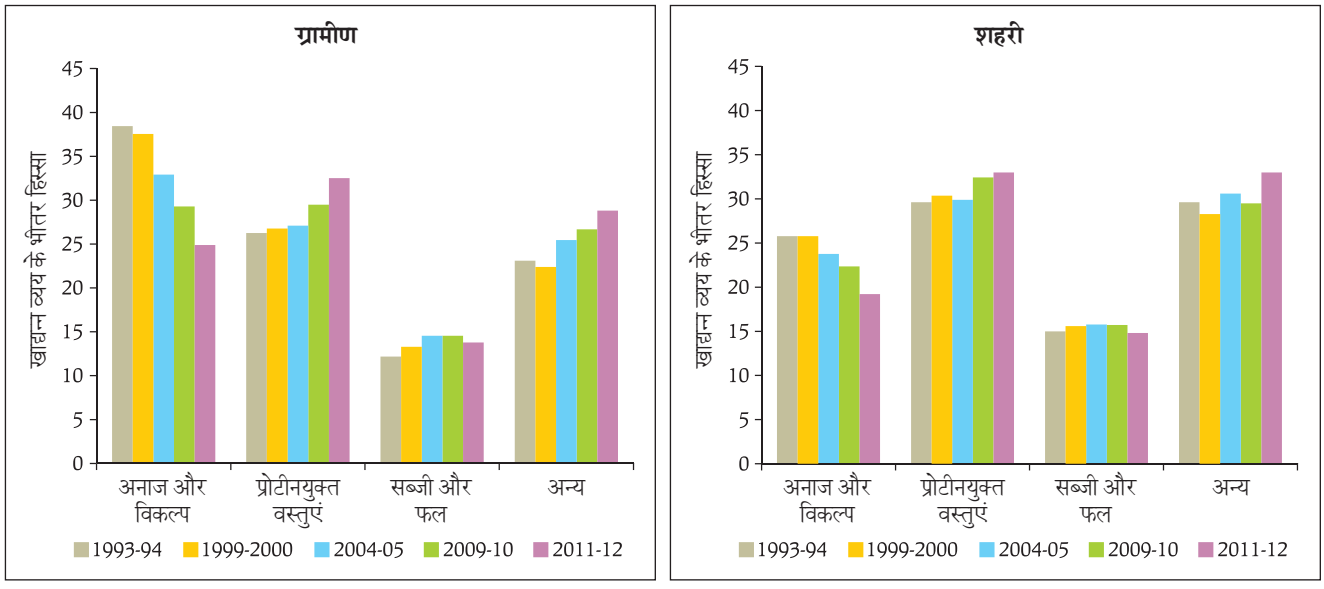

बाज़ार (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) में मूल्य-प्रवृत्ति को भी शामिल किया जाता है। एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलें थोक मूल्य सूचकांक में 'प्राथमिक सामग्री' की श्रेणी में एक तिहाई से अधिक का हिस्सा रखती हैं। चूंकि एमएसपी बाजार मूल्यों के लिए आधार होता है, और बाज़ार में जब तेजी अधिक हो जाती है तो कई बार यह सीधे ही बाज़ार-मूल्य को समायोजित कर देता है, प्रमुख फसलों के लिए मूल्यों में महंगाई की दर हाल के वर्षों में एमएसपी में हुई वृद्धि से जुड़ी हुई प्रतीत होती है (चार्ट 6)।

इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं, वह यह कि कृषिगत पण्यों के तुलनात्मक मूल्यों में बदलाव हुआ है, जो एमएसपी में वृद्धि से आगे बढ़ा है। तात्पर्य यह है कि बढ़ती हुई मांग जिसे हमने प्रलेख में दिखाया है, को पूरा करने के लिए यदि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जाना है तो यही वह ज़रुरत है जिसकी हमें आवश्यकता है। चार्ट 7 (ए) में हमने खाद्यान्न के थोक मूल्य सूचकांक के अनुपात के प्रति खाद्येतर मदों के थोक मूल्य सूचकांक अनुपात को हमने अंकित किया है। यह स्थिति कृषि के व्यापार में सराहनीय सुधार प्रदर्शित करती है।

चार्ट 5 : प्रति व्यक्ति मासिक आधार पर उपभोग की गई वस्तुएं - (किलोग्राम में)

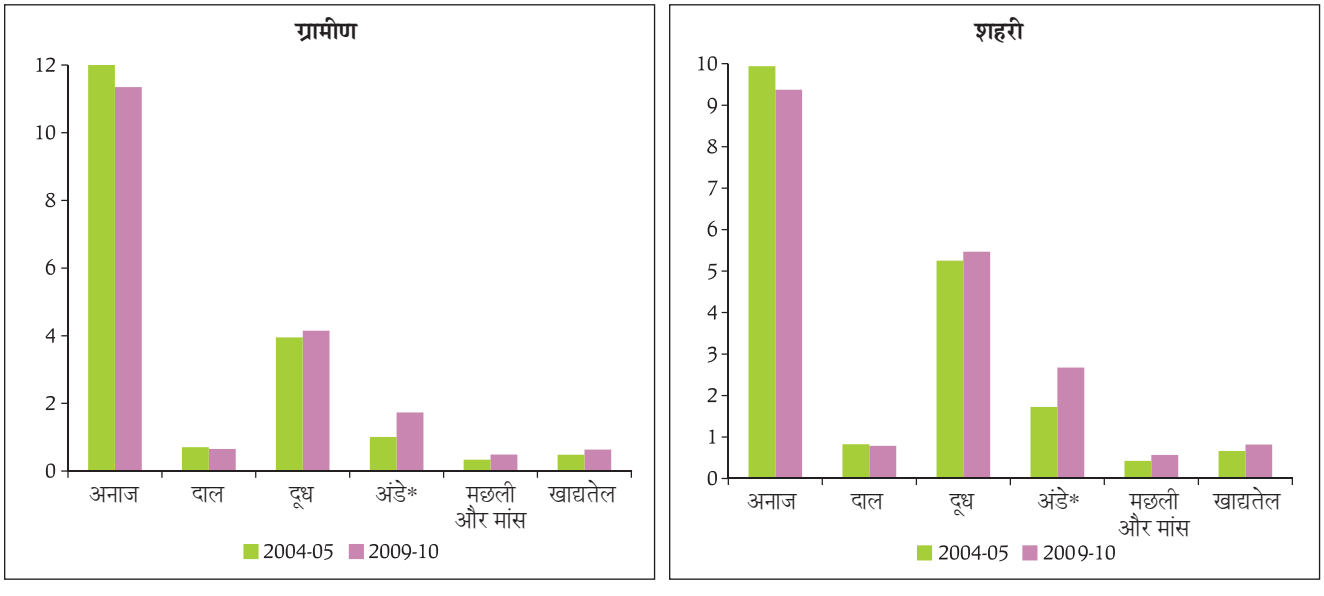

चार्ट 6 : वर्ष 2005-06 से 2012-13 के दौरान एमएसपी में परिवर्तन और मुद्रास्फीति

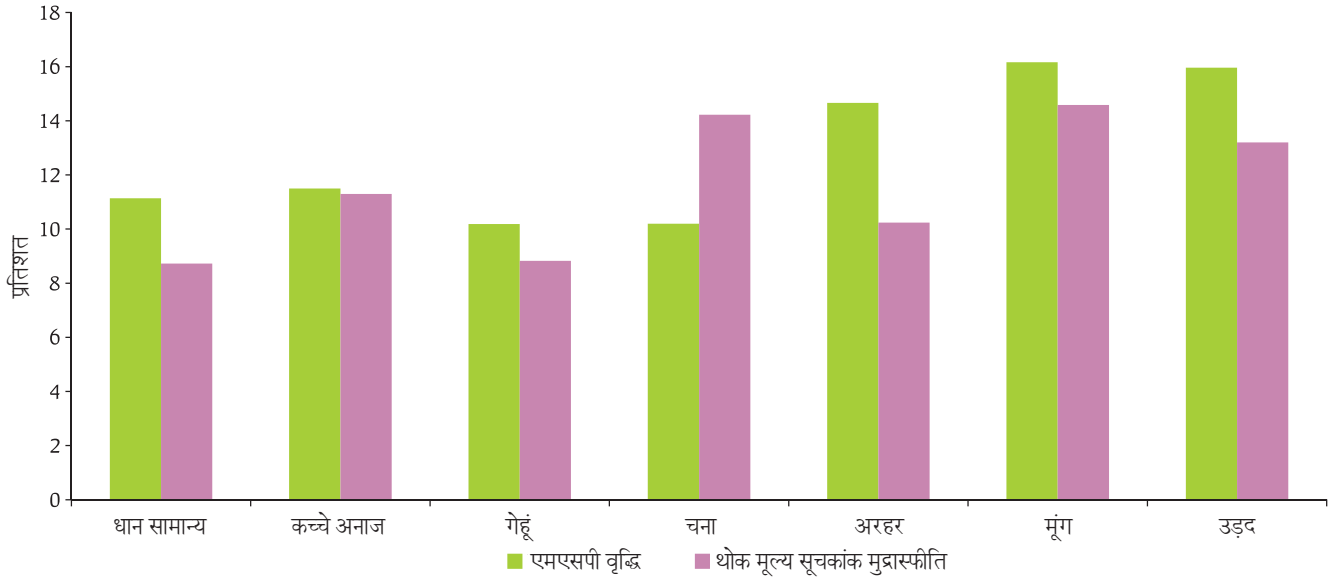

लेकिन जब हम प्राप्त सीएसीपी आंकड़ों के आधार पर इनपुट लागत में परिवर्तन के अनुपात की तुलना कृषि वस्तुओं के उत्पादन मूल्य से करते हैं तो पाते हैं कि वह बिल्कुल सपाट रहता है, जिसका मतलब है कि एमएसपी में वृद्धि से होने वाला फायदा कृषि क्षेत्र को पूरी तरह नहीं मिल पाया है क्योंकि इनपुट की लागतें बढ़ रही हैं। इससे यही पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि उतनी सुदृढ़ क्यों नहीं है। इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है?

इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि एमएसपी से भी इनपुट लागतें बढ़ती हैं; इसलिए बढ़ती हुई एमएसपी कुत्ते द्वारा अपनी पूंछ पकड़ने जैसा है - जो उसे कभी नहीं पकड़ सकता। अन्य व्याख्या यह हो सकती है कि चूंकि चावल और गेहूं खाने की प्राथमिक वस्तुएं हैं और एमएसपी पर हासिल की जाती हैं, इसलिए चावल और गेहूं का उत्पादन विकृत हो जाता है और किसान उनके मिले-जुले रूप में ही उप-इष्टतम उत्पादन ही कर पाते हैं - बहुत अधिक चावल और गेहूँ

चार्ट 7 : कृषि पण्यों का एमएसपी और आंतरिक व्यापार संबंध

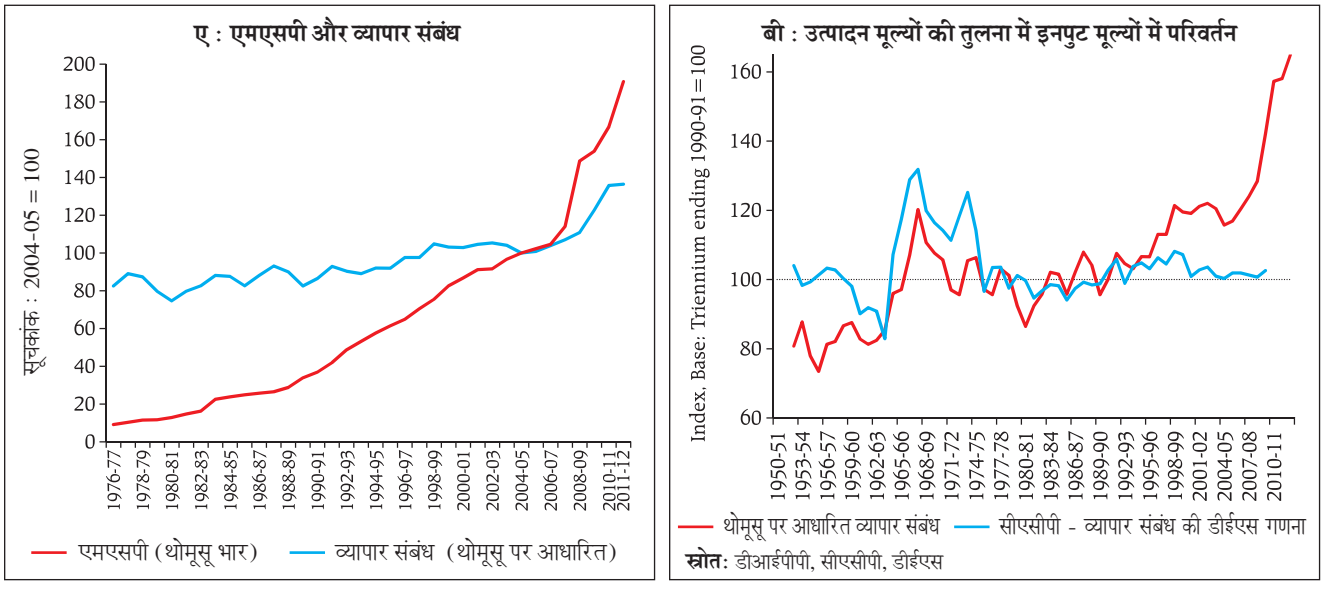

का उत्पादन और अन्य जरूरी चीजों का बहुत कम उत्पादन। इन दोनों व्याख्याओं से पता चलता है कि और अधिक संतुलन रखने की जरूरत है क्योंकि सरकार आने वाले महीनों में एमएसपी का निर्धारण कर देगी।

हालांकि, लागतों में वृद्धि के ब्योरे देखना उपयोगी होगा। कृषि इनपुट के मूल्य, साथ ही वेतन में, पिछले पांच वर्ष (2004-05 से 2007-08) की तुलना में 2008-09 के दौरान तीव्र वृद्धि हुई है जो 2012-13 तक जारी थी (सारणी 1)। संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

उदाहरण के लिए, मजदूरी में हुई वृद्धि धान की इनपुट लागतों में हुई अधिकांश वृद्धि का कारण थी (चार्ट 8)।

पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण मज़दूरी की सांकेतिक दर बहुत तेजी से बढ़ी है। क्योंकि बहुत से भारतीय कामगारों की जीविका मज़दूरी है, खाने की वस्तुओं के ऊंचे मूल्य ग्रामीण मज़दूरी की दर में वृद्धि करते हैं, और ऐसा होने के प्रमाण 2007 से पहले मौजूद हैं। किंतु, 2007 के बाद अर्थमितीय जांच से पता चलता है कि मज़दूरी की मूल्य के प्रति स्थिति हताहत करने वाली रही है, जो यह रेखांकित करती है कि ग्रामीण मज़दूरी, खाने की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का प्रमुख निर्धारक है। अतः ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि इतनी तीव्र क्यों रही है?

सारणी 1 : चुनिंदा कृषि इनपुट मूल्यों में वृद्धि

(वार्षिक औसत, प्रतिशत)

	2004-05 से 2007-08	2008-09 से 2012-13
खाद्य सामग्री	7.3	11.4
खाद्य और कीटनाशक	1.7	7.8
चारा	1.3	19.5
गोला (पशु आहार)	12.2	10.2
हार्ड स्पीड ड़ीजल	4.5	8.0
बिजली (कृषि)	2.3	8.7
ट्रैक्टर	3.6	5.4
मज़दूरी (औसत)	6.2	17.3

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय

बी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (मनरेगा)

ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किए जाने के बाद (प्रत्येक गृहस्थों के ऐसे वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार देने का आश्वासन जो अकौशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक हों) ग्रामीण मज़दूरी में बहुत ज़्यादा तेजी आ गई। हो सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण कामगारों की सौदेबाज़ी करने की शक्ति बढ़ा दी हो, किंतु सावधानी से किए गए अर्थमितीय अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसके कारण ग्रामीण मज़दूरी बहुत मामूली तौर पर बढ़ी है और सच तो यह है कि इसका कोई भी प्रभाव क्षय हो जाने वाला है (चार्ट 9)। ऐसा कहा जाता है, किंतु मनरेगा मज़दूरी के सूचकांकन से पता चलता है कि ग्रामीण मज़दूरी को बढ़ाने में इसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होने वाला है।

सी. ग्रामीण चलनिधि और ऋण

कृषि क्षेत्र को मिलनेवाली चलनिधि में वृद्धि हुई है, ज़मीन की बिक्री और कृषि को दिए जा रहे बढ़ते ऋण दोनों से

चार्ट 8 : धान की खेती की अस्थिर लागत

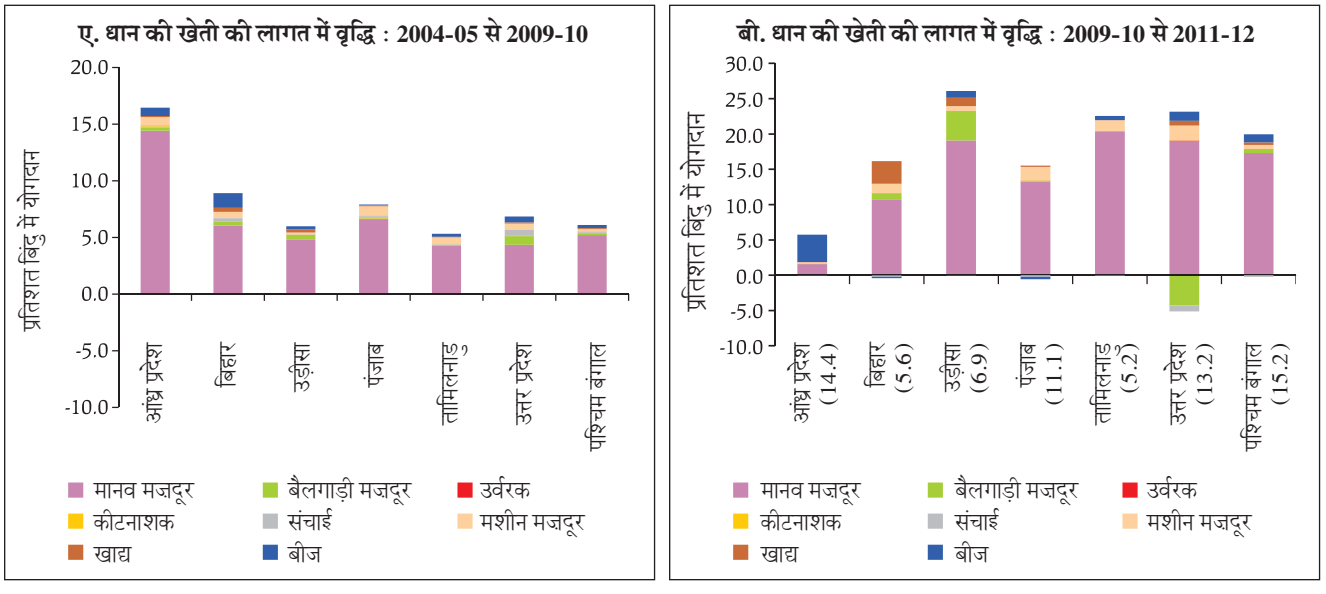

चार्ट 9 : ग्रामीण भारत में मज़दूरी और मूल्य में तुलनात्मक घट-बढ़

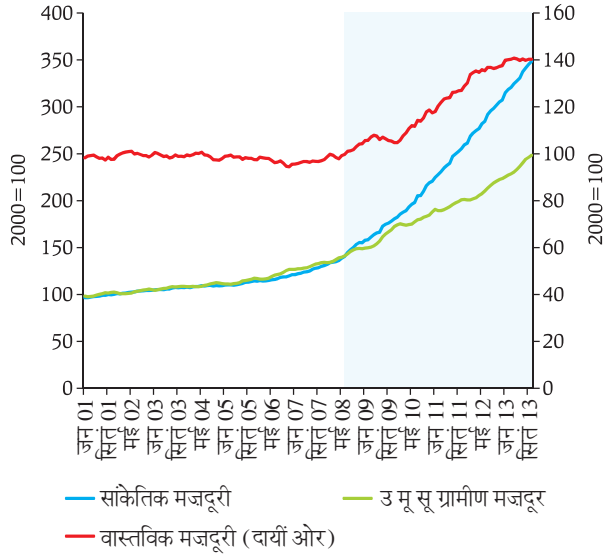

चार्ट 10 : कृषि क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से ऋण (बकाया) - कृषि से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

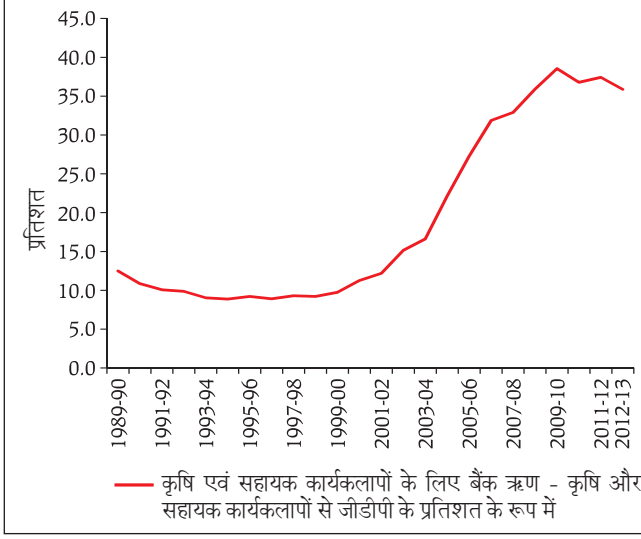

(चार्ट 10)। कृषि क्षेत्र को दिए जा रहे अधिक ऋण ने कृषि में निजी निवेश को काफी बढ़ा दिया है, लेकिन इसने ग्रामीण मज़दूरी में भी इज़ाफा कर दिया है।

डी. मज़दूरों का निर्माण की ओर जाना

मज़दूर लोग कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र, खासतौर से निर्माण कार्य की ओर जा रहे हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि ग्रामीण मज़दूरों की मज़दूरी दर बढ़ेगी (मज़दूरी की कमी के कारण), खासतौर से उन राज्यों में जिनसे मज़दूरों की आपूर्ति की जाती है। कृषि मज़दूरों की कुल संख्या घट गई है जो 2004-05 में 259 मिलियन से घट कर 2011-12 में 231 मिलियन रह गई है। कृषि क्षेत्र जो 1999-2000 में कुल रोजगार में से 60 प्रतिशत को रोजगार प्रदान करता था, अब 50 प्रतिशता से भी कम को रोजगार प्रदान कर रहा है (चार्ट 11, सारणी 2)।

चार्ट 11 : क्षेत्रवार रोजगार स्वरूप

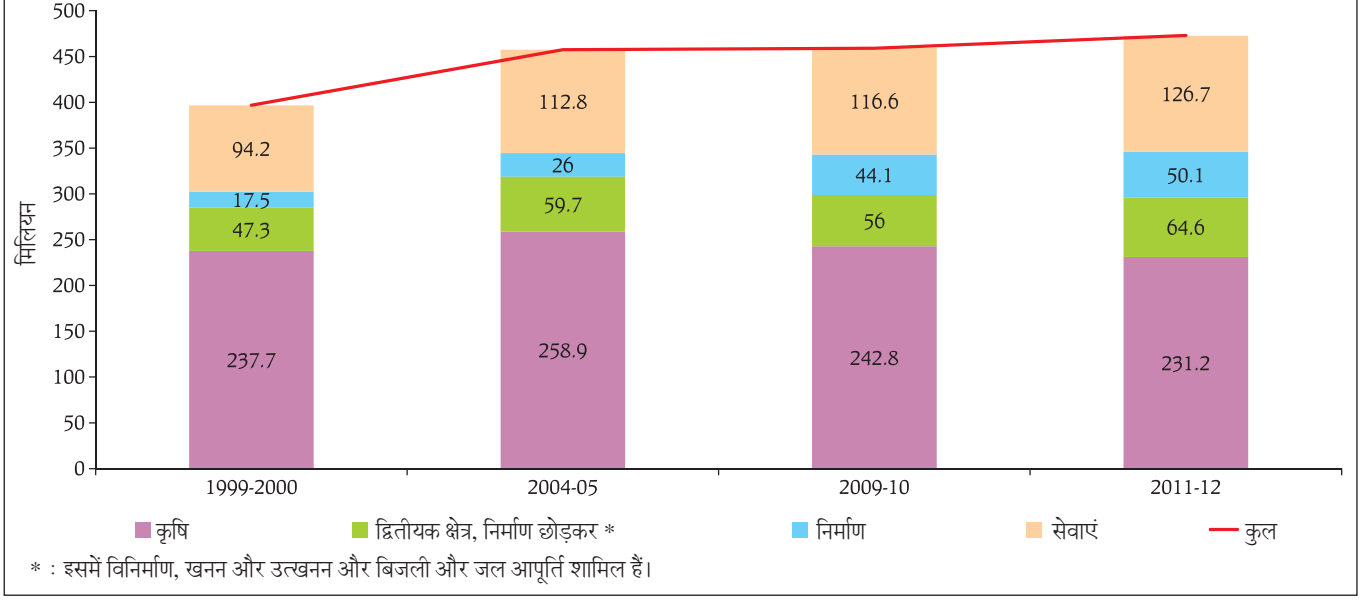

* : इसमें विनिर्माण, खनन और उत्खनन और बिजली और जल आपूर्ति शामिल हैं।

सारणी 2 : क्षेत्रवार रोजगार का हिस्सा

(प्रतिशत)

क्षेत्र	1999-2000	2004-05	2009-10	2011-12
कृषि	60	57	53	49
द्वितीयक क्षेत्र, निर्माण * को छोड़कर	12	13	12	14
निर्माण	4	6	10	11
सेवाएं	24	25	25	27
कुल	100	100	100	100

* इसमें विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, बिजली और जल आपूर्ति शामिल हैं।
स्रोत : एनएसएसओ और 12वीं योजना दस्तावेज

ई. महिला सहभागिता

ग्रामीण क्षेत्र में मज़दूरी बढ़ने की एक और दिलचस्प संभावित व्याख्या यह है कि ग्रामीण बाज़ारों में महिलाओं की सहभागिता में बदलाव आ गया है। सभी आयु-वर्ग में महिलाओं की सहभागिता की दर कम हो गई है। बढ़ते जीवन-स्तर की वजह से ग्रामीण परिवारों ने महिलाओं को श्रम-शक्ति से हटा लिया है (चार्ट 2)। बढ़ती हुई संपन्नता के कारण लोग लड़कियों (10 से 20 वर्ष की आयु-समूह की लड़कियां) की शिक्षा पर अधिक निवेश करने लगे हैं जिसकी वजह से भी श्रम-शक्ति में महिलाओं की सहभागिता कम हो गई है।

3. सारांश

संक्षेप में, जब हम खाद्यान्न की महंगाई की जांच करते हैं, तो इसका अधिकांश हिस्सा खाद्यान्न की बढ़ती उत्पादन-लागत में होता है, जो प्राथमिक रूप से मज़दूरी की महंगाई कहलाती है। उसमें से कुछ तो वास्तविक मज़दूरी में वृद्धि होता है, निर्माण, शिक्षा, घरेलू कार्य या मनरेगा से हटकर कृषि क्षेत्र की ओर मजदूरों को आकर्षत किया जा सके। यदि अन्य स्थानों पर भी मज़दूरी की दर बढ़ती है, तो कृषि क्षेत्र के कार्यों को आकर्षक बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत मज़दूरी दर में आवश्यक बदलाव नहीं लाया जा सकेगा और यह मज़दूरी दर का एक दुष्चक्र बनता जाएगा। कहीं-कहीं कृषि क्षेत्र में मज़दूरी दर में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि उन ग्रामीण क्षेत्रों को चलनिधि अधिक प्राप्त हो रही है। यह बात थोड़ी विरोधाभासी है, किंतु खाद्यान्न की महंगाई को नियंत्रित करने और खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाने के लिए आवश्यक है कि -

i) अन्य क्षेत्रों में मज़दूरी दर की वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए ताकि कृषि क्षेत्र में मज़दूरी में अपेक्षाकृत वृद्धि समग्र मज़दूरी में बहुत अधिक बढ़ोतरी के बिना हो सके।

ii) ग्रामीण क्षेत्र में मज़दूरी में अवांछित वृद्धि तथा अन्य कृषि संबंधी इनपुट लागतों (सब्सिडी के माध्यम से नहीं) को रोका जाए ताकि किसानों को अधिक प्रतिफल प्राप्त हो सके।

iii) खाद्यान्न की कीमतों को बाज़ार द्वारा निर्धारित होने दीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल न्यूनतम समर्थन स्तर को दी जाए

चार्ट 12: श्रमिक दल सहभागिता दर

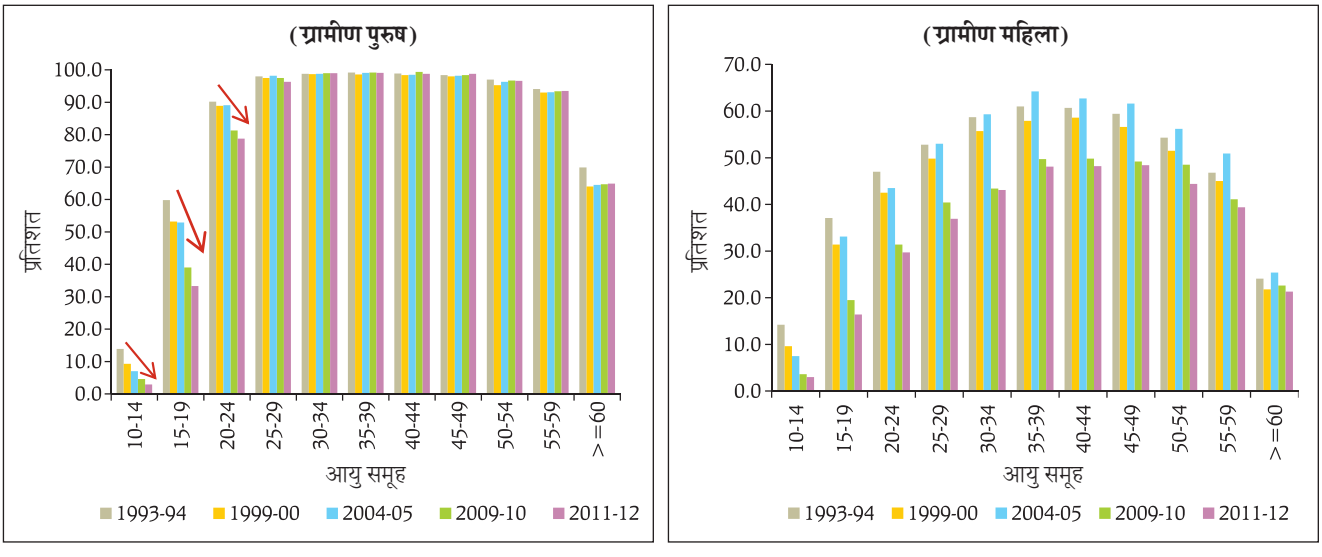

स्रोत: एनएसएसओ रोजगार और बेरोजगार सर्वेक्षण 2011-12

ताकि उत्पादन का स्तर मूल्य-मज़दूरी के दुष्चक्र में उलझकर न रह जाए। इसका आशय है कि एमएसपी में आगे बढ़ती हुई वृद्धि की गति को सीमित किया जाए।

iv) बिचौलियों की भूमिका, संख्या और एकाधिकार शक्ति को कम करते हुए (एपीएमसी अधिनियम संशोधन) तथा संभार-तंत्र को बेहतर बनाकर किसानों को मिलने वाले फायदे तथा गृहस्थों द्वारा किए जानने वाले भुगतान के अंतर को कम करना।

v) प्रौद्योगिकी में विस्तार करके, सिंचाई आदि से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बेहतर बनाना।

इन उपायों में से (i) और (ii) के संबंध में मौद्रिक नीति की सीधी भूमिका है वह यह कि मजदूरों की मांग करके तथा मुद्रास्फीति की प्रत्याशा को नियंत्रित करके मज़दूरी संबंधी सौदेबाजी को संतुलित बनाना। सच तो यह है कि शहरी अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने से, अब कुछ ऐसे सुबूत मिलने लगे हैं कि ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि कम हो गई है (चार्ट 13), हालांकि हाल के दिनों में हुई वृद्धि चिंता का कारण बनी हुई है।

अंतिम बात यह है कि हमारे खाद्यान्न के मूल्य काफी हद तक विश्व के मूल्यों से प्रभावित होने लगे हैं (पिछले वर्ष हम विश्व के सबसे बड़े चावल निर्यातक थे)। विश्व में खाद्यान्न के मूल्य संतुलित होने से घरेलू खाद्यान्न मूल्य में भी नरमी लाई जा सकती है - बशर्ते कि हम विश्व मूल्यों को अपने यहां के मूल्यों से जोड़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप न करें, और निर्यात या आयात पर सीमा-निर्धारण के लिए हस्तक्षेप न करें।

चार्ट 13: ग्रामीण क्षेत्रों में मज़दूरी और महंगाई

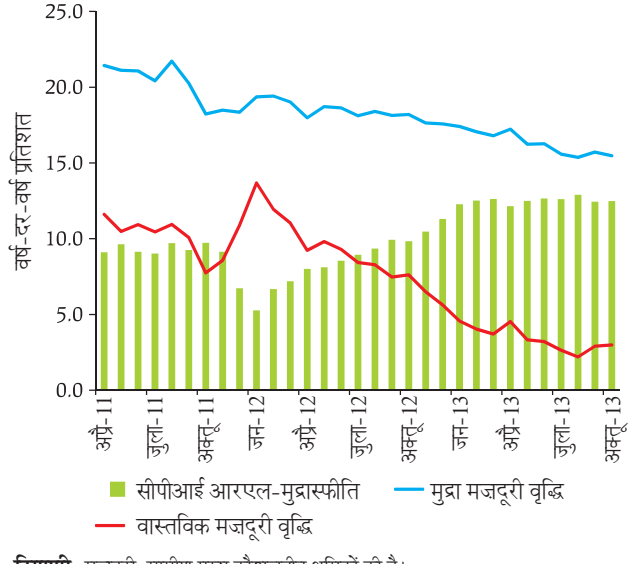

टिप्पणी: मजदूरी, ग्रामीण पुरुष कौशलहीन श्रमिकों की है।

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि भारतीय रिज़र्व बैंक ग्रामीण क्षेत्र की संपन्नता चाहता है और उचित ऋण और निवेश सुविधा के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना चाहता है। किंतु हाल के समय में मुद्रास्फीति की स्थिति ने किसानों के हाथों को मज़बूत करने में मदद नहीं की है, इसलिए मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ाई भी किसानों के हितों में है।

सारांश रूप में -

- चूंकि समृद्धि ने खाद्यान्न की मांग बढ़ा दी है, इसलिए हमें और अधिक खाद्यान्न के उत्पादन (अथवा आयात) की आवश्यकता है।
- कृषि वस्तुओं की अधिक कीमतें किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
- उन्होंने उत्पादन तो किया है किंतु वह पर्याप्त नहीं है। इसका आंशिक कारण यह हो सकता है कि किसानों की आमदनी उनके उत्पादन की ऊंची लागतों में लग जाती है, अधिकांशतः मज़दूरी देने में।
- ग्रामीण क्षेत्र में मज़दूरी में वृद्धि पर रोक लगाने के लिए, यह मानते हुए कि अन्य क्षेत्र की मजदूरी के समान इसमें वृद्धि करते हुए ताकि मजदूर कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित हों, अन्य क्षेत्रों में मजदूरी में अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
- मज़दूरी में वृद्धि, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में इसकी वृद्धि को रोकने के लिए मौद्रिक नीति बहुत ही उपयुक्त उपकरण है।
- ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी में धीमी वृद्धि कुछ हद तक कठोर नीति का परिणाम हो सकती है जो अन्य क्षेत्र में मजदूरी वृद्धि के लिए लागू की जाती है।
- निःसंदेह, अन्य मूल्य एवं मज़दूरी में वृद्धि को नियंत्रित करने (जैसे सेवाओं का मूल्य, जो उ मू सू का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है) के लिए मौद्रिक नीति को प्रभावशीलता बहुत ही कम विवादास्पद है।

निष्कर्षतः रिज़र्व बैंक यह विश्वास करता है कि मुद्रास्फीति के विरुद्ध लड़ाई कर्षण-शक्ति रखती है, बावजूद इसके कि खाद्यान्न उमूसू (सीपीआई) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।